कानपुर, शुक्रवार, 12 जून, 2026
वर्ष: 03, अंक: 144, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड 'गोल्डन बॉय' जसपाल राणा नहीं रहे...>Pg12

सिटी की खस्ताहाल सड़कों पर फूटा जनाक्रोश...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

यूपी में दौड़ी पहली हाइड्रोजन बस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को मिली 45 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए पहली बार हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्य परिवहन व्यवस्था को नई पहचान देने वाले इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। इनमें से 34 बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा से जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी, जबकि 11 इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ को दी गई हैं। इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तीन हाइड्रोजन बसों का संचालन भी शुरू किया गया है, जिन्हें एनटीपीसी ने उपलब्ध कराया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी भविष्य की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि इन बसों के लिए आवश्यक हाइड्रोजन सीवर के ट्रीटेड पानी से तैयार की जाएगी। वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, जबकि हाइड्रोजन को संपीड़ित कर ईंधन के रूप में बसों में इस्तेमाल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल प्रदूषण कम करने में सहायक होगी बल्कि ऊर्जा के वैकल्पिक और टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने बताया कि 15 जून से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन की तैयारियां तेज हो जाएंगी और यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बसों की संख्या जल्द ही 110 तक पहुंचाई जाएगी। आगामी वर्षों में इसे बढ़ाकर 500 बसों तक करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट तक मेट्रो सेवा शुरू होने तक ये बसें लाखों यात्रियों के लिए प्रमुख परिवहन साधन बनेंगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा।

- उत्तर प्रदेश में पहली बार हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू हुआ
- यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रारंभिक चरण में 3 हाइड्रोजन बसें चलेंगी
- कुल 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई
- जेवर एयरपोर्ट के लिए 34 इलेक्ट्रिक बसें समर्पित की गईं
- लखनऊ को 11 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली
- सीवर के ट्रीटेड पानी से हाइड्रोजन तैयार कर बसें चलाई जाएंगी
- बसों की संख्या बढ़ाकर पहले 110 और भविष्य में 500 तक करने की योजना है

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में खराब सड़कें, कमजोर कानून व्यवस्था और निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल था। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश में लगभग चार लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विकसित हुआ है, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने अयोध्या का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों तक उपेक्षा झेलने वाले इस धार्मिक नगर को अब महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आधुनिक आधारभूत संरचना और बेहतर कनेक्टिविटी ही विकसित उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है।

नई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों के संचालन से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही, जेवर एयरपोर्ट तक आसान, सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का रास्ता भी प्रशस्त होगा।

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन?

- ग्रीन हाइड्रोजन पानी से तैयार की जाती है
- उत्पादन प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है
- इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है
- इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है
- परिवहन, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है

यूपी की हरित परिवहन रणनीति

- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा।
- हाइड्रोजन आधारित परिवहन का प्रयोग।
- एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी पर फोकस।
- प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता।
- भविष्य में 500 बसों तक विस्तार की योजना।

जेवर एयरपोर्ट को क्या होगा लाभ?

- एयरपोर्ट तक निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी
- निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी
- यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम होगी
- ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण में कमी आएगी
- एयरपोर्ट क्षेत्र को 'ग्रीन मोबिलिटी जोन' के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी

दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में केडीए

पांच परिसरों के बेसमेंट सील

शहर के सभी बेसमेंट की हो रही है जांच

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। दिल्ली में बेसमेंट में हुई दुखद घटना के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शहर में नियमों के विपरीत संचालित गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केडीए की प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल, होटल और शैक्षणिक संस्थानों के बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर पांच परिसरों के बेसमेंट सील कर दिए।

केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक एवं सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देशन में प्रवर्तन जोन-4 क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया। उनके साथ अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, प्रवर्तन स्टाफ, विभागीय सुरक्षा बल तथा पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।जांच के दौरान ऐसे परिसरों को चिन्हित किया गया जहां बसमेंट का उपयोग स्वीकृत मानकों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर पांच परिसरों के बेसमेंट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

डॉ. रवि प्रताप सिंह का कहना है कि बेसमेंट का उपयोग केवल स्वीकृत मानकों और भवन उपविधियों के अनुरूप ही किया जा सकता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे के बाद प्राधिकरण ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और शहरभर में जांच अभियान जारी रहेगा।प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बेसमेंट में व्यवसाय संचालित करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'मुस्कान उत्सव 2026' को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, 150 से अधिक बच्चे करेंगे प्रतिभा प्रदर्शन

» आशा की किरण फाउंडेशन की कार्यकारी बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा, सतीश महाना होंगे मुख्य अतिथि

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आशा की किरण फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को गंगा क्लब, कानपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम मुस्कान उत्सव 2026 की तैयारियों, व्यवस्थाओं और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 जून 2026 को सायं 6:30 बजे से मर्चेंट्स चैंबर, कानपुर में आयोजित होगा।

कार्यक्रम में आशा की किरण फाउंडेशन के शिक्षा केंद्रों से जुड़े 150 से अधिक वंचित एवं जरूरतमंद बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इनमें नृत्य, संगीत, नाट्य मंचन और प्रेरणादायक प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी।

फाउंडेशन के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सपनों को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। संस्था का मानना है कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल सह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बैठक में फाउंडेशन के संरक्षक अनिल जैन, मानद सलाहकार प्रमोद पांडेय, अध्यक्ष विपुल जैन, महासचिव वैष्णवी सक्सेना, उपाध्यक्ष ऋषभ जैन, मीडिया प्रभारी अचिन अरोड़ा, कार्यक्रम संयोजक अनूप जैन, अमोद जैन एवं वीरेंद्र गुलाटी सहित अन्य पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

पदाधिकारियों ने बताया कि मुस्कान उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन बच्चों के संघर्ष, मेहनत और सपनों का उत्सव है जिन्हें संस्था वर्षों से निःशुल्क शिक्षा, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। वर्तमान में फाउंडेशन विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से सैकड़ों बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

भविष्य मालिका पुराण व श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन, डॉ. काशीनाथ मिश्र करेंगे कथावाचन

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

श्रीमद्भागवत कथामृत (जगन्नाथ संस्कृति), भविष्य मालिका पुराण एवं मानव कल्याणार्थ विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान एवं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित डॉ. काशीनाथ मिश्र कथा का वाचन करेंगे।आयोजकों के अनुसार भविष्य मालिका पुराण लगभग 600 वर्ष प्राचीन सभ्यतागत ग्रंथ है, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य अच्युतानंद दास एवं पंचसखा संतों की रचना माना जाता है। यह ग्रंथ मानवता के भविष्य, युग परिवर्तन तथा कलियुग से सतयुग के संक्रमण से जुड़े संकेतों का वर्णन करता है। डॉ. मिश्र इस ग्रंथ का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने वाले प्रथम विद्वान बताए जाते हैं।कथावाचन के दौरान वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव, प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक चुनौतियों तथा सामाजिक असंतुलन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। डॉ. मिश्र के अनुसार वर्ष 2025 से 2032 तक का कालखंड मानवता के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय हो सकता है।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल चुनौतियों की चर्चा करना नहीं, बल्कि परिवार और समाज के लिए आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना भी है। धर्म, सदाचार और ईश्वर के आश्रय को जीवन में संतुलन एवं सुरक्षा का आधार बताते हुए वे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देंगे।

सिटी की खस्ताहाल सड़कों पर फूटा जनाक्रोश, सुरक्षित सफर बना चुनौती

बढ़ते हादसों के बीच सड़क सुरक्षा इंतजामों और जवाबदेही की उठी मांग

प्रमुख संवाददाता

कानपुर। शहर की जर्जर सड़कों को लेकर आम जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक गड्ढों, टूटी सड़कों, जलभराव और सड़क सुरक्षा उपकरणों के अभाव ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम की उदासीनता के कारण सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही हैं और रोजाना हजारों लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में सड़क हादसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि समय पर सड़क मरम्मत और सुरक्षा उपाय किए जाते तो इन हादसों को रोका जा सकता था।

गोविंद नगर समेत विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हालात सबसे अधिक खतरनाक हैं। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे और उखड़ी सतहें किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। वहीं खराब सड़कों के कारण एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, जिससे जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल सुविधा का नहीं बल्कि जनसुरक्षा का गंभीर विषय है। उन्होंने टिकाऊ सड़क निर्माण, नियमित रखरखाव, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, रिफ्लेक्टरयुक्त संकेतक, लेन डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है।

इधर नागरिकों ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता परीक्षण तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। शहर में विभिन्न नागरिक संगठन भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं और प्रशासन पर प्रभावी कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं।

जनता का स्पष्ट संदेश है कि सुरक्षित सड़कें कोई सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का मूल अधिकार हैं और अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

डॉट नाला धंसने से प्रभावित क्षेत्र का विधायक अमिताभ ने लिया जायजा

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने शुक्रवार को लक्ष्मीपुरवा-खलवा क्षेत्र में डॉट नाला धंसने से उत्पन्न गंभीर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। नाला धंसने के कारण आसपास के कई मकान प्रभावित हो गए हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है।

⇨ लक्ष्मीपुरवा-खलवा क्षेत्र में कई मकान प्रभावित, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान विधायक ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रभावित परिवार को असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। विधायक ने भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मौके पर मौजूद जलकल विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को उन्होंने तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी।

इस दौरान स्थानीय नागरिक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता रामू कुशवाहा, रिंकू बाजपेई, आनंद साहू, शिनेष कुमार, धीरू पटेल, गुड्डू गुप्ता, अनवार, सोनू तथा पवन कनौजिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और त्वरित समाधान की मांग की।

323 करोड़ के फर्जी कंपनी घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। 323 करोड़ रुपये के चर्चित फर्जी कंपनी घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थीं और इनके माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिटर्न में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया।

पुलिस के अनुसार, फर्जी कंपनियों के जरिए कागजी लेन-देन दिखाकर करोड़ों रुपये का कर लाभ प्राप्त किया गया। इस पूरे नेटवर्क का संचालन सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। मामले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं।

यह मामला चकेरी थाने में दर्ज है और इसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। पुलिस ने अब तक इस घोटाले से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित की गिरफ्तारी को जांच में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल का कहना है कि घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

मेट्रो और नगर निगम मिलकर रोकेंगे जलभराव

नगर आयुक्त ने एक सप्ताह में मांगी संयुक्त रिपोर्ट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बरसात के मौसम से पहले शहर को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए कानपुर नगर निगम और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में जलभराव, पार्किंग सुविधाओं के एकीकरण और जनसंपर्क से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

कानपुर के कई इलाकों में मेट्रो की खुदाई से नल और नालियां ध्वस्त हो गई हैं जिससे जलभराव की संभावना है

बैठक में मुख्य अभियंता जैदी, मेट्रो परियोजना निदेशक अरविंद मीना, मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर अजहर सरताज, डीजीएम ऑपरेशन शिशिर कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि नगर निगम के सभी डिजिटल डिस्प्ले बोर्डों पर कानपुर मेट्रो से संबंधित जनहित सामग्री का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर निगम की प्रस्तावित पार्किंग ऐप में कानपुर मेट्रो की पार्किंग सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिकों को एक ही मंच पर पार्किंग संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके।

नगर आयुक्त ने बताया कि पार्किंग ऐप वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है और तैयार होने के बाद मेट्रो पार्किंग का एकीकरण किया जाएगा।बैठक के दौरान शहर के कई क्षेत्रों में मेट्रो निर्माण कार्यों के कारण उत्पन्न हो रही जलभराव की समस्या पर विशेष चर्चा हुई। गोविंद नगर के नंदलाल चौराहा, सेंट्रल स्टेशन परिसर, परेड चौराहा स्थित पीपीएन मार्केट क्षेत्र, डबल पुलिया से विजय नगर तथा विजय नगर से सीटीआई तक जलभराव की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया।

नगर आयुक्त ने नगर निगम और मेट्रो अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

साथ ही देवकी चौराहे पर क्षतिग्रस्त डॉट नाले की मरम्मत तथा लगभग 100 मीटर नाले की सफाई का कार्य भी एक सप्ताह के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए, ताकि मानसून के दौरान नागरिकों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि दोनों विभागों के समन्वय से शहर में जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाकर बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

सीएम ग्रिड परियोजनाओं में देरी पर

अफसरों को महापौर की चेतावनी

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में महापौर तथा नगर आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में सीएम ग्रिड परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति और कार्यों में हो रही देरी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, जल निगम और जलकल विभाग के अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली गई।

जनता की शिकायतों पर नगर निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक, बरसात से पहले सड़क, सीवर और जलापूर्ति कार्य पूरा करने पर जोर

मुख्य अभियंता सिविल सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि सीएम ग्रिड फेज-1 में पांच तथा फेज-2 में पांच प्रमुख सड़कों पर कार्य चल रहा है। इनमें एनएच-19 से हमीरपुर रोड, बर्रा बाईपास से मेट्रो लाइन, बाबा कुटी चौराहा मार्ग, बगिया क्रासिंग से केसा कार्यालय तथा घंटाघर से ग्रीन पार्क मार्ग सहित कई महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं।बैठक में महापौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि परियोजनाओं के शिलान्यास को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अधिकांश कार्य अभी तक अधूरे हैं। जनता लगातार धूल, जलभराव, पेयजल आपूर्ति बाधित होने और यातायात अवरोध जैसी समस्याओं की शिकायत कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और जनता को राहत देने के निर्देश दिए।जल निगम के अधिशासी अभियंता मोहम्मद अजमल ने बताया कि घंटाघर से ग्रीन पार्क मार्ग पर भूमिगत केबलों की पहचान न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद सीवर और जलापूर्ति लाइन का कार्य 25 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बगिया क्रासिंग से केसा कार्यालय मार्ग पर शेष सीवर कार्य के कारण एक लेन 30 जून तक चालू करने की योजना है।बर्रा बाईपास-कर्रही रोड परियोजना में 500 मीटर सीवर लाइन के निस्तारण की समस्या सामने आई है, जिसके समाधान में लगभग दो माह लग सकते हैं। नगर आयुक्त ने स्वरूप नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई सामग्री, पाइप और गार्डर खुले में पड़े होने पर नाराजगी जताई तथा बरसात से पूर्व उन्हें हटाने और सभी निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि बारिश के दौरान जलभराव रोकने के लिए प्रत्येक जोन में पर्याप्त मड पंप उपलब्ध रखे जाएंगे। महापौर ने कहा कि अनावश्यक चौड़े फुटपाथों की समीक्षा कर सड़क की उपयोगी चौड़ाई बढ़ाई जाए और निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

जनता को कब मिलेगी राहत?

विशेषज्ञों के अनुसार सीएम ग्रिड परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके साथ सीवर, जलापूर्ति, ड्रेनेज और भविष्य की केबल डक्ट व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि भूमिगत कार्य पूर्ण होते ही सीआरआरआई के स्वीकृत डिजाइन के अनुसार सड़क निर्माण तेजी से किया जा सकता है। यदि विभागों के बीच बेहतर समन्वय बना रहा तो आगामी कुछ महीनों में शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं बरसात के दौरान जलभराव और कीचड़ की समस्या से निपटना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती रहेगा।

क्यों अटक रही हैं सीएम ग्रिड परियोजनाएं?

- भूमिगत केबलों का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।
- सीवर और जलापूर्ति लाइनों के पुर्नस्थापन में देरी।
- कई स्थानों पर नई सीवर लाइन की आवश्यकता।
- टेंडर प्रक्रिया में बाधाएं और निविदाएं न मिलना।
- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी।
- बरसात से पहले कार्य पूर्ण करने का बढ़ता दबाव।

एक नजर में....

- सीएम ग्रिड फेज-1 और फेज-2 की कुल 10 सड़कों की समीक्षा हुई।
- महापौर ने कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई।
- घंटाघर-ग्रीन पार्क मार्ग का कार्य 25 जून तक पूरा करने का लक्ष्य।
- बगिया क्रासिंग-केसा कार्यालय मार्ग की एक लेन 30 जून तक चालू होगी।
- बर्रा बाईपास मार्ग पर सीवर निस्तारण सबसे बड़ी चुनौती।
- सभी निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग अनिवार्य करने के निर्देश।
- बरसात से पहले मिट्टी के ढेर और निर्माण सामग्री हटाने का आदेश।

सम्पादकीय

सशक्तीकरण के दावे हकीकत भी बनें

यूं तो भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम दावे गाहे-बगाहे किए ही जाते हैं। आधी दुनिया को पूरा हक देने की बात होती है। किंतु-परंतु के बीच उन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जतायी जाती है। लेकिन इन दावों के बीच सामने आया एक कड़वा सच हमें वास्तविक स्थिति से रूबरू करा देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि शहरों की तुलना में ज्यादा शांत व सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर तक कह दिया। यहां तक कि घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कल्पित आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हुए उसे नजरअंदाज न करने की सलाह दी। यह विडंबना ही है कि जिन महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट नेशन बिल्डर बता रहा है, उन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर महिला सशक्तीकरण के सारे विशेष प्रयास सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा हेतु तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। इसमें दो राय नहीं कि समय-समय पर महिला उत्थान के लिये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चलाये जाते रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीवन के हर क्षेत्र में वे अपना आकाश तलाश रही हैं। विधायिका में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल सहमत नजर आते हैं। सवाल यही है कि जीवन व्यवहार में स्थिति क्यों नहीं बदलती।देश के नीति-नियंताओं को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौथी व शहरी क्षेत्र में हर छठी स्त्री को हिंसा व यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि घर से लेकर बाहर तक वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? क्या कहीं इसमें पितृसत्ता प्रधान समाज की मानसिकता कारण है? दरअसल, आज लड़कियों व महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूपों में मौजूद है। आजादी के सात दशक बाद भी हम दहेज के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये हैं। हाल के दिनों में दहेज हत्या के कई बहुचर्चित मामले प्रकाश में आए। एक लड़की की पढ़ाई से लेकर शादी तक मां-बाप काफी खर्च करते हैं, फिर दहेज देने की जरूरत क्यों? छोटी-छोटी बातों में महिलाओं से मारपीट की खबरें आती हैं। वहीं अदिवासी व पिछड़े इलाकों में महिलाओं को डायन बताकर मारने की घटनाएं सामने आती हैं। जिसके चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आते हैं। सर्वेक्षण का यह तथ्य चौंकाता है कि 18 से 49 आयु वर्ग की विवाहिताओं में बाईस फीसदी को वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हालांकि, समय के साथ हिंसा के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन ?इसके बावजूद स्थिति चिंता पैदा करती है। जो किसी सभ्य समाज के माथे पर एक दाग की तरह ही है। हमारी व्यवस्था की विसंगतियां, पुरुष प्रधान सोच और हिंसा रोकने के लिये बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में खामियां महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने में बाधक हैं।

शी के उत्तर कोरिया दौरे से सतर्क अमेरिका

क्षमा शर्मा

जिस परमाणु ताकत की आशंका को लेकर ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उत्तर कोरिया के मामले में चुप्पी है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं, कि उत्तर कोरियाई लीडरशिप के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। ट्रम्प उत्तर कोरिया के मुंहफट.जिस परमाणु ताकत की आशंका को लेकर ट्रम्प ने ईशन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उत्तर कोरिया के मामले में चुप्पी है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं, कि उत्तर कोरियाई लीडरशिप के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। ट्रम्प उत्तर कोरिया के मुंहफट नेता से दूरी बनाये रखना चाहते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने तेजी से अपना परमाणु शस्त्रागार बढ़ाया है।उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने चीनी राष्ट्रपति के दौरे को काफी कवरेज दिया, लेकिन दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग आदान-प्रदान बढ़ाने पर शी की बातों को शामिल नहीं किया।

सोल में हंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ़ फॉरेन स्टडीज़ में चीनी अध्ययन के प्रोफ़ेसर कांग जून-यंग ने कहा, कि शी की बातों से वाशिंगटन को यह संदेश मिला कि पेइचिंग ने 'मजबूती से एक मिलिट्री सहयोगी बना लिया है' प्रोफ़ेसर कांग जून-यंग ने फ्योंगयांग और मॉस्को के बीच 'बहुत ज़्यादा मिलिट्री नज़दीकी के प्रति सावधानी' का संकेत भी दिया। वाशिंगटन इस बार सतर्क है, मास्को की नज़र भी शी के आगमन पर थी।चीन और उत्तर कोरिया के बीच मिलिट्री सहयोग बढ़ने की संभावना ऐसे समय में बनी है, जब फ्योंगयांग अपने न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियारों के प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते शी के दौरे की घोषणा से एक दिन पहले, उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि किम ने हाल ही में न्यूक्लियर मटीरियल बनाने वाले एक नए प्लांट का दौरा किया, और न्यूक्लियर ताकत को तेज़ी से मजबूत करने का वादा देश से किया था।जिस परमाणु ताकत की आशंका को लेकर ट्रम्प ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उत्तर कोरिया के मामले में चुप्पी है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं, कि उत्तर कोरियाई लीडरशिप के विरुद्ध एक शब्द बोल दें। ट्रम्प उत्तर कोरिया के मुंहफट नेता से दूरी बनाये रखना चाहते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने तेजी से अपना परमाणु शस्त्रागार बढ़ाया है, और एक परमाणु-सम्पन्न राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया है। उत्तर कोरिया ने हमेशा चीन और रूस के बीच बराबर की दूरी बनाए रखने वाली कूटनीति अपनाई है, या दोनों के बीच संतुलन बनाकर चला है, इसलिए वह चीन के साथ ऐसे किसी भी मिलिट्री सहयोग को लेकर सतर्क है, जो 'रेड लाइन' को पार करता हो।26 अप्रैल, 2026 को, उत्तर कोरिया ने 'विदेशी सैन्य अभियानों का स्मारक संग्रहालय' खोला। यह संग्रहालय उन सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक ऐसी 'आत्मघाती सैन्य नीति' की पुष्टि की है जिसके तहत रूस-यूक्रेन युद्ध में शामिल सैनिकों को पकड़े जाने से बचने के लिए युद्ध के मैदान में आत्महत्या करनी होगी। इसी साल फरवरी में, दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने खबर दी थी, कि रूस-यूक्रेन युद्ध में 6,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए, या घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने बताया, कि फरवरी, 2026 तक, रूस के अग्रिम मोर्चे वाले कुर्स्क ओब्लास्ट में लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात थे। इनमें से 10,000 लड़ाकू सैनिक थे, और 1,000 इंजीनियरिंग सेवा के सैनिक थे।उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की ताकत रूस और चीन की वजह से है। उसी बूते वो गाहे-बगाहे ट्रम्प को ललकारते हैं, चुनांचे किम जोंग उन, पुतिन और शी दोनों से समान संतुलन बनाये रखना चाहते हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने कहा, 'रूस में 6,000 सैनिकों के हताहत होने के बावजूद, उत्तर कोरियाई सेना ने युद्ध के मैदान में आधुनिक युद्ध-कौशल और डेटा हासिल करने के साथ-साथ रूस की तकनीकी मदद से अपने हथियार प्रणालियों को अपग्रेड करने में सफलता पाई है।' एजेंसी ने यह भी बताया, कि फ्योंगयांग ने एक नया यूएवी ड्रोन विभाग बनाया है, और वह ऐसे सिस्टम को स्थापित करने पर काम कर रहा है, जो ड्रोन विकसित करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हो।लेकिन, क्या उत्तर कोरिया यह सार्वजानिक रूप से स्वीकार करेगा, कि उसके ड्रोन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है? फ्योंगयांग द्वारा अपने ड्रोन का ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। उत्तर कोरिया की नीति हमेशा हथियारों के गुप्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने की रही है। इसके बजाय, वे इस तरह के मामलों में रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखना पसंद करते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि उत्तर कोरिया और ईरान के बीच ड्रोन और मिसाइल तकनीक का गहरा आदान-प्रदान रहा है। कई उत्तर कोरियाई ड्रोन, ईरान के शाहेद सीरीज के ड्रोन्स से काफी मिलते-जुलते हैं।सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों को 'कूटनीति, कानून प्रवर्तन और सैन्य मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए'।

राजनीतिक सोच की गरीबी का त्रास झेलता पंजाब

राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है।पंजाब में पिछले कुछ सालों में राजनीति मुनाफा कमाने का एक ऐसा धंधा बन गया है, जिसमें लोगों के लिए काम करने की जगह व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीतिक दल बदली एक आम प्रक्रिया हो गई है।

चुनाव जीतने के लिए किसी राजनीतिक प्रेरणा या पॉलिसी के बजाय पैसे, पावर और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल आम हो गया है।अपने नुमाइंदे चुनते समय, राजनीतिक पार्टियां उसकी राज्य में जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण, बिगड़ती शहरी सेवाओं, हेल्थ और एजुकेशन को सही दिशा देने के लिए लोगों के हित में एक ठोस पॉलिसी बनाने की क्षमता के बजाय चुनाव क्षेत्र में उसके परिवार के कंट्रोल और पैसे खर्च करने की उसकी क्षमता और सहमति को प्राथमिकता दे रही हैं।आज़ादी के बाद से लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सत्ता की अदला-बदली करते रहे हैं, लेकिन 2022 से पॉलिटिकल पावर का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास है; जबकि भविष्य में भाजपा राज्य की बागडोर संभालने के लिए बेचैन हो रही है। सरकार द्वारा पंजाब को आर्थिक कर्ज़ से आज़ाद करने और लोगों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कोई पक्का प्रोग्राम बनाने के बजाय, राज्य में मुफ़्त आटा, दाल, मुफ़्त बिजली, मुफ़्त बस यात्रा, मुफ़्त तीर्थयात्रा और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मुफ़्त देने वगैरह का लालच देकर थोड़े समय की लोकप्रियता हासिल की जा रही है। टिकाऊ सुधारों के बजाय तुरंत चुनावी फ़ायदे को तरजीह दी जा रही है, लेकिन न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने से बचा जा रहा है। पंजाब के 'दस उंगलियों से काम करने और बांटकर खाने' वाले उसूल को कमज़ोर किया जा रहा है और लोगों को बेकार बनाया जा रहा है।दूसरी तरफ़, भाजपा के नेता 'डबल इंजन सरकार' का नारा लगा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि अगर उन्हें देश के खाते से कुछ पाना है, तो राज्य में उसी पार्टी को चुना जाए, जिसकी केंद्र में सरकार हो। यानी भाजपा केंद्र से आर्थिक सहायता का

लालच देकर पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में है। भाजपा वादा कर रही है कि अगर वह चुनाव जीतती है, तो राज्य में धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून बनाएगी। कुछ समय पहले भाजपा ने राज्य में कांग्रेस के फ्रंटलाइन नेताओं का पार्टी परिवर्तन कर के अपनी पार्टी में शामिल किया था, वहीं हाल ही में उसने आप के 6 राज्यसभा सदस्यों को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा लिया।गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यों के पार्टी परिवर्तन से कुछ दिन पहले ही उनमें से एक सदस्य के घर पर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने छापा मारा था और अगले ही दिन उन की पार्टी परिवर्तन की घटना हो गई।दूसरी तरफ आप में पंजाब के 6 में से 2 पार्टी परिवर्तन वाले सदस्य गैर पंजाबी हैं। राजनीति में अनजान और कच्ची समझ रखने वाले, लेकिन उस समय आप ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक को हीरो की तरह पेश करके, उन्हें पंजाब में बिना किसी संवैधानिक दायित्व के बहुत ज़्यादा पावर, राज्य के खर्च पर सिक्योरिटी देकर, और फिर उन्हें पंजाब से राज्यसभा मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट करके अपनी पॉलिटिकल नादानी दिखाई है। अगर हम पंजाब के बारे केंद्र सरकार की पॉलिसी देखें, तो हमें वहां भी राजनीतिक गुरबत ही दिखाई देती है। भाजपा की केंद्र सरकार, लोगों की भलाई से ज़्यादा कॉर्पोरेट के फ़ायदे के लिए, पंजाब में खेती को इंडस्ट्रिलाइज़ेशन करने और इसमें लगी 35-40 फीसदी आबादी के एक बड़े हिस्से को खेती के पेशे से हटाने का इरादा रखती है, लेकिन इस आबादी के लिए एक विकल्प के तौर पर एक ठोस और सम्मानजनक काम के लिए कोई भरोसेमंद पॉलिसी लाने में कोई सीरियस नहीं दिखती।राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं द्वारा 'डबल इंजन सरकार' और 'धर्मांतरण विरोधी कानून' की पेशकश भी राज्य में राजनीतिक नासमझी को दर्शाती है।आप के राज्यसभा मेंबरों ने अपने दलबदल को यह कहकर सही ठहराया है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था। लेकिन सच तो यह है कि उनके पास न तो कोई लोगों का एजेंडा था, न सोच और न ही पक्का यकीन और न ही लोगों के हित में कुछ कहने का दम; अगर कुछ था, तो वह था पद और पावर की भूख। लालच और डर के कारण, दलबदल करने से उनका दम घुटना तो रुक गया, लेकिन लोगों के भरोसे का दम ज़रूर घुट गया।

भाजपा उनके कंधों पर सवार होकर 2027 का चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। ऐसी सोच पॉलिटिकल गरीबी का ही एक नमूना है।राजनीतिक गुरबत का एक और उदाहरण यह है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों की नाकामियों के भरोसे अपनी जीत पक्की मान रही है, और उसके सभी नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जताते हुए एक-दूसरे से ही मुकाबले में हैं। ऐसे में, पंजाब के राजनेताओं का 'तूफान और दहाड़' और उनकी 'तू-तू, मैं-मैं' किसी भी सैद्धांतिक राजनीति से खाली है, जिसकी वजह से पंजाब गरीबी की ओर बढ़ता दिख रहा है।

प्रशासन ने दिखाया पूरा प्लान

बाढ़ आई तो ऐसे बचेगी जान

बीआरडी कॉलेज में बनाया गया राहत शिविर, कई विभाग के अफसर शामिल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। नानामऊ घाट के किनारे बसी बस्ती में मदद के लिए लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। सूचना मिलते ही बिल्हौर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीमें सक्रिय हो गईं। नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और मवेशियों को भी सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर बिल्हौर के बाबा रघुनंदन दास इंटर कॉलेज में राहत शिविर पूरी तरह तैयार था। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कमरे, भोजन बनाने के लिए किचन, चिकित्सा सुविधा के लिए एंबुलेंस और राहत सामग्री वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे थे। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम एक मॉकड्रिल का हिस्सा था, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी मानो क्षेत्र में वास्तव में बाढ़ आ गई हो।

मानसून से पहले संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए गुरुवार को बिल्हौर तहसील प्रशासन ने बृहद मॉकड्रिल का आयोजन किया। बिल्हौर उपजिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में आयोजित अभ्यास में विभिन्न विभागों और राहत एजेंसियों ने आपदा के दौरान की जाने वाली कार्रवाई का प्रदर्शन किया। नानामऊ घाट क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। जहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया दिखाई गई। इसके बाद राहत शिविर में प्रभावित लोगों को ठहराने, भोजन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्थाओं का प्रदर्शन किया गया। मॉकड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, राजस्व, स्वास्थ्य, पशुपालन, खाद्य एवं रसद समेत विभिन्न विभागों ने भाग लिया। अधिकारियों ने आपदा की स्थिति में विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का भी परीक्षण किया। तहसीलदार अनुभव चंद्रा, नायब तहसीलदार सीपी राजपूत, रंजीत यादव, एसीपी बिल्हौर ने लोगों से अपील की कि बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नं. और संबंधित विभागों से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई।

वीडियो कॉल पर तैयारियां दिखाते एसडीएम मनीष कुमार।

बाढ़ जैसी आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मॉकड्रिल के माध्यम से सभी विभागों की तैयारियों और आपसी समन्वय को परखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनहानि और नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके — मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी, बिल्हौर

बाढ़ मॉकड्रिल में राहत एवं बचाव अभियान के लिए मुस्तैद पुलिस बल।

एसडीएम ने संभाल लिया 'लाइव कवरेज' का मोर्चा

बाढ़ मॉकड्रिल के दौरान प्रदेश स्तर के अधिकारी मोबाइल वीडियो कॉलिंग के जरिए जिलों और तहसीलों की तैयारियों का लाइव निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही स्क्रीन पर बिल्हौर का नंबर आया, एसडीएम मनीष कुमार ने कैमरा संभाल लिया और पूरे राहत शिविर की ऐसी लाइव प्रस्तुति दी कि कुछ देर के लिए माहौल किसी न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट जैसा हो गया।मोबाइल कैमरे के साथ वह राहत शिविर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे और अधिकारियों को बताते रहे कि यहां महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है, यहां पुरुषों के लिए कक्ष बनाए गए हैं, इस स्थान पर भोजन तैयार किया जा रहा है, यहां एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीम मौजूद है। कैमरे के सामने वह जिस आत्मविश्वास और सहजता से व्यवस्थाओं का ब्यौरा दे रहे थे, उससे लग रहा था मानो किसी टीवी चैनल का संवाददाता बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हो। उनकी प्रस्तुति के दौरान अधिकारियों ने न केवल व्यवस्थाओं को करीब से देखा, बल्कि बिल्हौर तहसील की तैयारी और समन्वय की भी सराहना की।

राहत शिविर में दिखाई गई पूरी व्यवस्था

बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठहराने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बीआरडी इंटर कॉलेज परिसर में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किया गया। शिविर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग आवास कक्ष बनाए गए थे। भोजन तैयार करने और वितरण के लिए अस्थायी किचन की व्यवस्था की गई थी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर तैनात रही। राहत सामग्री वितरण केंद्र भी संचालित किया गया, जहां जरूरतमंदों तक आवश्यक सामान पहुंचाने की व्यवस्था दिखाई गई। इसके अलावा पशुओं के सुरक्षित ठहराव के लिए अलग स्थान चिन्हित किया गया था। प्रभावित लोगों के पंजीकरण और सहायता के लिए विशेष काउंटर भी स्थापित किए गए। जिससे राहत कार्यों का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

मॉकड्रिल के तहत बनाए गए महिला आश्रय कक्ष में मौजूद महिला लेखपाल व महिलाएं।

फास्टैग के नाम पर मांगा एक्सट्रा चार्ज, वीडियो वायरल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे स्थित निवादा टोल प्लाजा पर फास्टैग लगाने के नाम पर वाहन चालकों से मनमाने शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में टोल प्लाजा कर्मी द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक रकम मांगने का दावा किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

⇨ निवादा टोल प्लाजा पर 400 की जगह 600 रुपये मांगने का आरोप

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति फास्टैग बनवाने का शुल्क पूछता है, जिस पर टोल प्लाजा पर मौजूद युवक कुल 600 रुपये बताता है। जब उससे शुल्क का विवरण मांगा जाता है तो वह 100 रुपये फास्टैग, 200 रुपये सिक्योरिटी और 100 रुपये टैग कॉस्ट बताता है। कुल 400 रुपये का हिसाब देने के बाद शेष 200 रुपये के बारे में पूछने पर युवक उसे अपना बैठने और लगाने का चार्ज बताता है। वीडियो में वाहन स्वामी अतिरिक्त 200 रुपये की रसीद की मांग करता है, लेकिन कर्मचारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद फास्टैग के नाम पर अवैध वसूली के आरोप चर्चा का विषय बन गए हैं स्थानीय वाहन चालकों का आरोप है कि टोल प्लाजा पर लंबे समय से फास्टैग बनवाने वालों से निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूली जा रही है। उनका कहना है कि अधिकांश लोग विवाद से बचने के लिए शिकायत नहीं करते, जिससे यह व्यवस्था लगातार चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी।

किसानों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगी नव निर्वाचित डायरेक्टर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के कानपुर मंडल की नव निर्वाचित डायरेक्टर सुमन लता सचान का गुरुवार को बिल्हौर आगमन पर बैंक पदाधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ में हुए चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद वह पहली बार क्षेत्र में पहुंचीं।

स्वागत समारोह का नेतृत्व बिल्हौर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष डॉ. रामपाल कटियार और चौबेपुर-शिवराजपुर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष सुरेंद्र दीक्षित ने किया। इस दौरान उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर तथा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, बैंक कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुमन लता सचान ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को शासन और उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा तथा उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर डॉ. रामपाल कटियार ने बैंक की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि जब उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी, तब बैंक बंद होने की स्थिति में पहुंच गया था। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 से 2025 के बीच 134 किसानों को लाभान्वित करते हुए 3.10 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया।

उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत 110 किसानों को लगभग 2.10 करोड़ रुपये की छूट दिलाई गई, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिलने के साथ बैंक की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हुई।

डॉ. कटियार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कम राशि के ऋण के लिए भी किसानों की पूरी भूमि बंधक हो जाती है, जिससे भविष्य में अन्य जरूरतों के लिए ऋण लेने में कठिनाई होती है। इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने खाद की निर्धारित सीमा से किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया। बताया कि इस संबंध में कृषि मंत्री से वार्ता की जा चुकी है और जल्द ही सर्वे कराकर व्यावहारिक समाधान निकाले जाने का आश्वासन मिला है। वहीं सुरेंद्र दीक्षित ने कहा कि भूमि विकास बैंक का प्रत्येक निर्णय किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाएगा।

शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, मोहन भागवत सुरक्षित

कानपुर से दिल्ली जा रहे थे संघ प्रमुख, घटना में कोई यात्री घायल नहीं, सुरक्षा बढ़ाकर ट्रेन को रवाना किया गया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फिरोजाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की यात्रा के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है।

जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान फिरोजाबाद के पास ट्रेन के एक कोच पर पत्थर आकर लगा।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि मोहन भागवत ई-1 कोच में सीट संख्या 39 और 40 पर यात्रा कर रहे थे।

पथराव के दौरान पत्थर कोच की सीट संख्या 50 के समीप बाहरी शीशे से टकराया। पत्थर केवल बाहरी ग्लास पर लगा, जिससे शीशे को मामूली क्षति पहुंची, लेकिन किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत किया गया तथा संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई।

एहतियात के तौर पर सुरक्षा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई, जिसके बाद ट्रेन को निर्धारित गंतव्य नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पथराव की घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि घटना में किसी यात्री की सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद वीआईपी ट्रेनों और महत्वपूर्ण यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। रेलवे प्रशासन ने दोषियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

सीएम डैशबोर्ड में जालौन पुलिस का जलवा प्रदेश में हासिल किया पांचवां स्थान

लगातार 15वीं बार टॉप-10 जिलों में बनाई जगह, एसपी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

जालौन। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मई माह के सीएम डैशबोर्ड में जालौन पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसेवा से जुड़े विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट कार्य के दम पर जालौन ने एक बार फिर अपनी प्रभावी पुलिसिंग का लोहा मनवाया है।पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद पुलिस लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यही कारण है कि जालौन को लगातार 15वीं बार कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रदेश के टॉप-10 जिलों में स्थान मिला है। इस उपलब्धि ने न केवल पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है, बल्कि जनपद का नाम भी प्रदेश स्तर पर रोशन किया है।सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग 51 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर तय की जाती है। इनमें अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, डायल-112 की प्रतिक्रिया अवधि, महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई, एनडीपीएस एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाना सहित कई अहम बिंदु शामिल हैं।

जालौन पुलिस ने विशेष रूप से महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और डायल-112 की त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ने भी जिले की रैंकिंग को मजबूती प्रदान की।

जनपद पुलिस की इस उपलब्धि को जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुख पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। जिलेवासियों ने भी इस सफलता पर खुशी जताते हुए पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। अधिकारियों का कहना है

अदलाबाद में आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल, बाढ़ राहत एवं बचाव तैयारियों को परखा गया

प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व विभाग, पुलिस, एसएसबी के जवानों ने हिस्सा लिया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। संभावित बाढ़ आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से गुरुवार को तहसील निघासन अंतर्गत ग्राम पंचायत अदलाबाद में आपदा राहत एवं बचाव मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। शारदा नदी के किनारे आयोजित इस अभ्यास में प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व विभाग, पुलिस तथा एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया।मॉकड्रिल के दौरान बाढ़ की काल्पनिक स्थिति तैयार कर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। बचाव दलों ने नावों और अन्य सुरक्षा उपकरणों की सहायता से नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा उन्हें राहत शिविर तक पहुंचाने का अभ्यास किया। इसके साथ ही आपदा के दौरान अपनाई जाने वाली त्वरित कार्रवाई और समन्वित प्रयासों की भी जानकारी दी गई।कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), एसडीएम राजीव निगम, कोतवाल

अदलाबाद गांव समीप मार्कड्रील करवाते अधिकारी।

अवधराज सिंह सेंगर, लेखपाल तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बचाव कार्यों का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया। इस दौरान 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की रैपिड रिस्पांस टीम ने भी बाढ़ राहत एवं बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। जवानों ने आपदा के समय उपयोग में आने वाले उपकरणों और रेस्क्यू तकनीकों का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया।

फार्मेसी परीक्षा ड्यूटी में घोटाले के आरोप, मुख्यमंत्री से जांच की मांग

ड्यूटी आवंटन में पक्षपात और अवैध वसूली का आरोप, फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने खोला मोर्चा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन (ABPA)
(Approved by Government of India) Area of Operation : All India
शाखा – उत्तर प्रदेश

पत्रांक : ABPA/UP/2026/0052 — दिनांक 10/06/2026

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार

विषय -प्राविधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी जांच और दोषियों की बर्खास्तगी की कार्यवाही किए जाने के संबंध में

महोदय,
उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रयोगात्मक की परीक्षाएं संचालित हो रही है, जिसमें परिसर कार्यालय द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षकों की ड्यूटी में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई है व नियमों के विपरीत ड्यूटी लगाई गई है। सूत्रों से पता चला कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की सचिव डॉ संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, पिछले वर्ष प्रमुख सचिव एम. देवराज की शक्ति और निवर्तमान सचिव अजीत कुमार मिश्रा द्वारा यह निर्देश स्पष्ट रूप से जारी किया गया की लिखित परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन किए हुए परीक्षकों की ड्यूटी प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएगी उसी की तर्ज पर परीक्षकों की ड्यूटी आवंटित हुई परंतु इस वर्ष लिखित परीक्षाओं का मूल्यांकन किए हुए शिक्षकों को दरकिनार तमाम ऐसे परीक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई जिनके द्वारा लिखित परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया गया था इस आवंटन में बड़े पैमाने पर एक रैकेट द्वारा कार्य किया गया जिसके द्वारा प्रति कॉलेज 6 से 10 हजार रुपए प्रति कॉलेज तक की अवैध वसूली की गई। परिषद कार्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा की कॉपियों को आवंटन करने में भी खुलेआम अनुभाग अधिकारी द्वारा 500 रूपये प्रति संस्था की अवैध वसूली भी की गई। प्रकरण अत्यंत गंभीर और भ्रष्टाचार से व्याप्त है जिसमें बड़े पैमाने पर परिषद की संलिप्तता रही है। प्रदेश के हजारों परीक्षकों की ड्यूटी में की गई अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी व्याप्त है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है की प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाने में बरती गई अनियमितता अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को लेकर जांच कमेटी बनाने व दोषियों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्यवाही किए जाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि -
1-आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
2-प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश
3- महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश
4-अपर मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार

शिव कुमार
प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ/अयोध्या। फार्मेसी की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ड्यूटी आवंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्राविधिक शिक्षा परिषद पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने आरोप लगाया कि परिषद द्वारा पहले यह नियम बनाया गया था कि लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को ही प्रयोगात्मक परीक्षा ड्यूटी में प्राथमिकता दी जाएगी।

लेकिन जारी सूची में कई पात्र शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रयोगात्मक परीक्षा से जुड़े कार्यों में संस्थानों से प्रति संस्था 500 रुपये तक की अवैध वसूली की गई। एसोसिएशन का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस प्रकरण ने प्राविधिक शिक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नोन नदी के नाले में मिले जीवित मोर्टार को जांच के लिए ले गई सेना

गजनेर क्षेत्र में दहशत का माहौल, सेना की तकनीकी रिपोर्ट से खुलेगा रहस्य कि घातक सैन्य सामग्री आखिर यहां तक कैसे पहुंची

स्वराज इंडिया FOLLOW UP

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव के पास नोन नदी से जुड़े नाले में मिला जीवित मोर्टार सेल अब सेना की विस्तृत जांच के दायरे में पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को बाराबंकी सैन्य छावनी से पहुंची सेना की विशेषज्ञ टीम गजनेर थाने से मोर्टार को अपने साथ ले गई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सेना के जवान इसे सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए रवाना हुए। अब तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह खतरनाक सैन्य विस्फोटक आखिर कहां से आया और नाले तक कैसे पहुंचा।घटना का खुलासा

जांच में किन बिंदुओं पर रहेगा फोकस?

- » मोर्टार का निर्माण स्थल और वर्ष।
- »सीरियल नंबर के आधार पर उसकी पहचान।
- »किस सैन्य इकाई या भंडारण से संबंध।
- »दुर्घटनावश खोया गया या अवैध रूप से पहुंचाया गया।
- »नाले में पहुंचने की संभावित समयावधि।
- »सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की संभावना।
- »किसी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि से जुड़े होने की जांच।

बुधवार को उस समय हुआ जब जसवापुर गांव के कुछ युवक नाले का पानी पंपिंग सेट से निकालकर मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान दलदली हिस्से में उन्हें एक संदिग्ध धातु की वस्तु दिखाई दी। वस्तु को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गजनेर पुलिस

मोर्टार सेल क्या होता है?

- » मोर्टार एक प्रकार का सैन्य विस्फोटक हथियार होता है।
- »इसे कम दूरी से ऊंचे कोण पर दागा जाता है।
- »जीवित मोर्टार में विस्फोटक सामग्री सक्रिय अवस्था में होती है।
- »ऐसे गोले वर्षों तक जमीन या पानी में दबे रहने के बाद भी खतरनाक बने रह सकते हैं।
- »विशेषज्ञों के अनुसार इन्हें बिना सुरक्षा उपायों के छूना जानलेवा हो सकता है।

मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी।मामले की गंभीरता को देखते हुए झांसी से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पुष्टि की कि बरामद वस्तु एक जीवित मोर्टार सेल है।

इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने सभी सुरक्षा

08 www.swarajindianews.com | कानपुर देहात | स्वराज इंडिया

नोन नदी के नाले में मिला मिसाइलनुमा उपकरण

बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद मची हलचल

गजनेर क्षेत्र के जसवापुर के पास मिला संदिग्ध धातु उपकरण

» झांसी से पहुंची बम निरोधक टीम ने सुरक्षित कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव के समीप नोन नदी से जुड़े एक नाले में बुधवार को मिसाइलनुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मछली पकड़ रहे कुछ युवकों की नजर पानी में पड़ी एक भारी धातु की वस्तु पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं।

मानकों का पालन करते हुए मोर्टार को विशेष सुरक्षा बॉक्स में रखा और पुलिस अभिरक्षा में गजनेर थाने में जमा करा दिया।

बृहस्पतिवार को बाराबंकी सैन्य छावनी से पहुंची सेना की टीम ने मोर्टार को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। सेना के विशेषज्ञ मोर्टार के सीरियल नंबर, निर्माण संबंधी पहचान, निर्माण तिथि और अन्य तकनीकी तथ्यों की बारीकी से जांच करेंगे।

इससे यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि यह किस सैन्य इकाई या स्थान से संबंधित है तथा किन परिस्थितियों में यहां पहुंचा।

जीवित मोर्टार मिलने की खबर से पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के निकट इतनी खतरनाक सैन्य सामग्री का मिलना चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने तथा यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सभी की निगाहें सेना की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

ट्रैक्टर से नीचे गिरी किशोरी की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर खेतों की ओर जारी किशोरी ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के चलते ट्राली से नीचे जा गिरी। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि कहिंजरी निवासी मीना देवी की 12 वर्षीय पुत्री रोली मजदूरी करने के लिए अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की ओर जा रही थी।

इसी दौरान कहिंजरी स्थित बालाजी मोटर्स के सामने अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से सड़क के नीचे जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया। स्थानीय लोग आनन फानन में घायल रोली को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवली लेकर रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कहिंजरी चौकी प्रभारी प्रवीण कृष्णा मिश्रा ने बताया कि मामला जानकारी में आया है हालांकि परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

» राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, किसानों-छात्रों-महिलाओं की समस्याओं, नीट, जीडी पेपर लीक और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय माती पर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा की अगुवाई में हुए धरना प्रदर्शन में भारी भीड़ देखने को मिली। सपा के जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान की

अगुवाई में बड़ी संख्या में उनके समर्थक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ यदुनाथ सिंह, शिवम सेंगर, शफीक खान, शरीफ कुरेशी, मो अख्तर,आहिल खान, अजीजुर रहमान, रहीश अली, शफीक उर्फ ललई ,इमरान अहमद, शोएब अख्तर ,वशी अहमद, लाडले गफ्फारी, अशीष यादव ,अनुज यादव एडवोकेट आदि रहे। सफल धरना प्रदर्शन के लिए जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान ने सभी का आभार प्रकट किया।

जिला कारागार अब बन रहा आदर्श सुधार गृह

डेढ़ हजार बंदियों को मिल रहा रोजगारपरक प्रशिक्षण, सुधार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कभी केवल सजा और बंदीकरण के लिए पहचानी जाने वाली जिला कारागार कानपुर देहात अब एक आदर्श सुधार गृह के रूप में नई पहचान बना रही है। यहां निरुद्ध लगभग डेढ़ हजार महिला एवं पुरुष बंदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कारागार प्रशासन के कुशल नेतृत्व और नवाचारों के चलते बंदियों को न केवल अनुशासित वातावरण मिल रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

जिला कारागार के अधीक्षक धीरज कुमार सिन्हा एवं डिप्टी जेलर डॉ. राजेश कुमार के नेतृत्व में बंदियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

जेल मैनुअल के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं शिक्षा, कौशल विकास और नैतिक मूल्यों पर आधारित

कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सुधार की राह पर बढ़ रहे बंदी

कारागार प्रशासन द्वारा विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे बंदी रिहाई के बाद

आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। प्रेरणादायी प्रसंगों, सामाजिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें बेहतर नागरिक बनने की सीख दी जा रही है।

इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है और कई बंदी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्पित हुए हैं।

आज भी याद किए जाते हैं डॉ. विजय पांडेय

जिला कारागार में विकास कार्यों और सुधारात्मक पहल के लिए पूर्व जेलर डॉ. विजय कुमार पांडेय का योगदान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके कार्यकाल में कारागार में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए, जिनकी सराहना आज भी की जाती है। अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ कार्य करने वाले डॉ. पांडेय की प्रेरणा से अनेक बंदियों ने नशे की लत छोड़कर नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया था।

शांतिपूर्ण वातावरण में गढ़े जा रहे बेहतर नागरिक

अधीक्षक धीरज कुमार सिन्हा और डिप्टी जेलर डॉ. राजेश कुमार के प्रयासों से जिला कारागार का वातावरण अनुशासित, शांतिपूर्ण और सुधारोन्मुख बना हुआ है। प्रशासन का लक्ष्य केवल बंदियों को निरुद्ध रखना नहीं, बल्कि उन्हें समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में तैयार करना है। यही कारण है कि कानपुर देहात जिला कारागार आज प्रदेश के आदर्श सुधार गृहों में अपनी अलग पहचान स्थापित करता नजर आ रहा है।

बाढ़ आपदा से निपटने को प्रदेशभर में मॉक ड्रिल

37वीं वाहिनी पीएसी ने दिखाया दम

मानसून पूर्व तैयारियों की परखी गई क्षमता, पीएसी, एसडीआरएफ प्रशासन और अन्य एजेंसियों ने किया संयुक्त अभ्यास

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज-2026 का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुलिस महानिदेशक पीएसी उत्तर प्रदेश आलोक सिंह के निर्देशन तथा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के दिशा-निर्देशों के तहत हुआ।

पीएसी मुख्यालय द्वारा आयोजित इस व्यापक अभियान में प्रदेश के 44 संवेदनशील जनपदों की 118 तहसीलों में पीएसी की 17 वाहिनियों की सात कंपनियों एवं एक प्लाटून तथा एसडीआरएफ की 16 टीमों ने भाग लिया।

अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान विभिन्न एजेंसियों की समन्वित कार्यप्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता तथा संसाधनों की कार्यशीलता का परीक्षण करना था।

इस अभियान में 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर नगर के सेनानायक बजरंगबली चौरसिया के नेतृत्व में वाहिनी के 'बी दल' (बाढ़ राहत दल) ने पांच जनपदों में मॉक ड्रिल और रेस्क्यू प्रदर्शन किए। कानपुर नगर में पीसी. प्रकाश यादव के नेतृत्व में घाटमपुर तहसील क्षेत्र में अभ्यास किया गया। कानपुर देहात में पीसी. जगतसिंह यादव के हमराह थाना अमरहर क्षेत्र स्थित यमुना नदी में रेस्क्यू अभ्यास हुआ।

उन्नाव में पीसी. अरविंद सिंह के नेतृत्व में जमालनगर नहर क्षेत्र में तैयारियों का परीक्षण किया गया। हमीरपुर में पीसी. शिव प्रसाद के हमराह बेतवा नदी के उत्तरी पुल किनारे तथा जालौन में पीसी. वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कालपी क्षेत्र की यमुना नदी में सफल मॉक ड्रिल की गई।

अभ्यास के दौरान नाव संचालन, लाइफ जैकेट के उपयोग, रस्सियों के माध्यम से बचाव, प्राथमिक उपचार तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों को आपदा के समय सतर्कता एवं बचाव उपायों की जानकारी भी दी गई। डीजी पीएसी आलोक सिंह ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीएसी एवं एसडीआरएफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा के लिए सदैव तैयार हैं। इस मॉक एक्सरसाइज में जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

13 लाख माफ चालान फिर होंगे सक्रिय परिवहन विभाग शुरू करेगा समीक्षा

» सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने बदला रुख, गंभीर मामलों की होगी दोबारा जांच

» जिला स्तरीय समितियां करेंगी छंटनी, करीब चार लाख मामलों में जुर्माना या सजा की संभावना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच माफ किए गए करीब 13 लाख वाहन चालानों को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीर यातायात उल्लंघनों से जुड़े मामलों में एकमुश्त माफी पर चिंता जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने इन चालानों की पुनर्समीक्षा का फैसला लिया है। इसके तहत परिवहन विभाग को सभी संबंधित मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित

करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पहले एक विशेष निर्णय के तहत लंबित ई-चालानों और यातायात उल्लंघनों से जुड़े मामलों को व्यापक राहत देते हुए समाप्त कर दिया था। इस फैसले से लाखों वाहन स्वामियों को राहत मिली थी, लेकिन बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने विशेष रूप से उन मामलों पर चिंता व्यक्त की जिनमें सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराध शामिल थे और जिन्हें बिना श्रेणीकरण के माफ कर दिया गया था।

अब परिवहन विभाग प्रत्येक जिले में एक विशेष समिति का गठन करेगा। ये समितियां पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा कर चालानों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगी। इनमें गंभीर यातायात अपराध, सामान्य उल्लंघन तथा अन्य प्रशासनिक प्रकृति के मामले शामिल किए जाएंगे। समीक्षा के बाद जिन मामलों को गंभीर श्रेणी में पाया जाएगा, उन्हें दोबारा सक्रिय किया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, लगभग चार लाख मामलों में दोबारा सुनवाई, जुर्माना वसूली अथवा कानूनी कार्रवाई की संभावना है। इनमें ओवरलोडिंग, खतरनाक ड्राइविंग, बिना वैध दस्तावेज वाहन संचालन और सड़क सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े प्रकरण शामिल हो सकते हैं।

परिवहन विभाग जल्द ही सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके बाद समितियां रिकॉर्ड का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जाएगी जिनका सार्वजनिक सुरक्षा से सीधा संबंध है। इससे यातायात नियमों के प्रभावी पालन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्नाव में 55 फ्लैटों के लिए आवेदन शुरू, मात्र 3.59 लाख रुपये में मिलेगा अपना घर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास पाने का सपना देख रहे पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकसित उन्नाव के मगरवारा स्थित गोकुलधाम आवासीय परियोजना में बचे हुए 55 फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।केडीए के उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक एवं सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में विशेष कार्याधिकारी एवं उप जिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह द्वारा योजना की समीक्षा कर अवशेष फ्लैटों को आवंटन के लिए चिन्हित किया गया है। यह परियोजना मेसर्स ट्रेड स्टोन लिमिटेड द्वारा मगरवारा (मिर्जा गेट-1 के निकट) उन्नाव में विकसित की गई है।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक फ्लैट का कार्पेट एरिया 23.12 वर्गमीटर है। फ्लैट की कुल कीमत 6.09 लाख रुपये निर्धारित है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी को केवल 3.59 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

केडीए के अनुसार इच्छुक एवं पात्र आवेदक 15 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक एचडीएफसी बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट

आकार का फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

प्राधिकरण ने बताया कि सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले आवेदकों के बीच नियमानुसार लॉटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा, जिसकी सूचना बाद में अलग से प्रकाशित की जाएगी।यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

लखनऊ एयरपोर्ट पर बम की सूचना से मचा हड़कंप, इंडिगो विमान की घंटों चली तलाशी

» टॉयलेट में ÒBOMBÓ लिखा टिशू पेपर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, 180 यात्रियों को उतारकर की गई सघन जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली जाने के लिए तैयार इंडिगो के एक विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को टेकऑफ से रोककर वापस एप्रन पर लाया गया और उसमें सवार सभी 180 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

सूत्रों के अनुसार इंडिगो का विमान सुबह करीब 10ः45 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और विमान उड़ान की अंतिम तैयारियों में था। इसी दौरान केबिन क्रू को विमान के शौचालय में एक टिशू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में 'ब्लहस्क' लिखा हुआ था। यह देखते ही चालक दल के सदस्यों ने तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। विमान को रनवे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया। इसके बाद यात्रियों को उनके सामान सहित नीचे उतारा गया और विमान, कार्गो क्षेत्र तथा सभी बैगों की आधुनिक उपकरणों की मदद से गहन तलाशी ली गई।

कई घंटों तक चली जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों को विमान के भीतर या आसपास कोई भी विस्फोटक, बम अथवा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार यह किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश प्रतीत होती है। सुरक्षा क्लीयरेंस मिलने के बाद ही विमान को उड़ान की अनुमति दी जाएगी।

घटना के कारण यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। दोपहर साढ़े बारह बजे तक विमान उड़ान नहीं भर सका था। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि टॉयलेट में 'ब्लहस्क' लिखा टिशू पेपर किसने रखा था।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस, युवती की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बारातियों से भरी एक बस हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि कई बाराती झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और विवाह समारोह का माहौल गम में बदल गया।बताया जाता है कि मोहल्ला पट्टी रामदास निवासी मोईन खान की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पीलीभीत जनपद के भिखारीपुर गांव से बारात बस द्वारा आ रही थी। जैसे ही बस मोहल्ले के समीप पहुंची, वह सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। संपर्क होते ही बस में करंट फैल गया और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बस से छलांग लगा दी।

हादसे में जीनत (20) गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मोहम्मद शादमान (12), शायरा बानो (48), अनाबिया (7), अमजद हुसैन (51), शायदा बेगम (60), सानिया (20), इशरत तथा बस चालक ताहिर सहित कई लोग करंट की चपेट में आने से झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

फतेहपुर में ट्रक ने डंपर में मारी टक्कर युवक की मौत, दो गंभीर घायल

» लोधीगंज के पास देर रात हुआ हादसा, पुलिस ने राहत-बचाव कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फतेहपुर। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना लोधीगंज के पास उस समय हुई, जब तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे डंपर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बारिश के बीच पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया।

जानकारी के अनुसार प्रयागराज निवासी तीन लोग डंपर से बड़वारी सैनी की ओर जा रहे थे। रात करीब दो बजे उनका वाहन सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डंपर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए।

हादसे में जैसिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप मौर्य और सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस, एंबुलेंस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से राहत अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया।जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। जैसिर की मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों की तेज रफ्तार आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।

दुधवा में 30 जून तक गूंजेगा जंगल सफारी का रोमांच

» पर्यटन सत्र 15 दिन बढ़ा, बाघ, गैंडा और बारासिंघा देखने का मिलेगा अतिरिक्त अवसर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति पर्यटन के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुधवा टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र अब निर्धारित अवधि से 15 दिन अधिक संचालित किया जाएगा। शासन के निर्देशों के बाद पर्यटक अब 30 जून तक दुधवा के घने जंगलों में सफारी का रोमांच उठा सकेंगे। इस निर्णय से उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अब तक बुकिंग न मिलने अथवा अन्य कारणों से दुधवा की यात्रा नहीं कर पाए थे।दुधवा टाइगर रिजर्व ने इस पर्यटन सत्र में लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बाघों की बेहतर साइटिंग, एक सींग वाले गैंडों की मौजूदगी, हाथियों के झुंड और दुर्लभ बारासिंघों के दर्शन ने देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

पार्क प्रशासन के अनुसार जून माह के अंतिम दिनों में जंगल के जलस्रोतों के आसपास वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। गर्मी के मौसम में जानवर पानी की तलाश में अधिक दिखाई देते हैं, जिससे पर्यटकों को वन्यजीवों को नजदीक से देखने का बेहतर अवसर मिलता है। यही कारण है कि पर्यटन सत्र बढ़ाने के निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है।दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर राजा मोहन ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में पर्यटन गतिविधियां 30 जून तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पर्यटकों की सुरक्षा, बेहतर सुविधाओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास सफल रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

पर्यटन सत्र बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। होटल व्यवसाय, गाइड सेवा, स्थानीय परिवहन और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। वन्यजीव विशेषज्ञों और फोटोग्राफरों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर बताया है।

एक नजर में...

- दुधवा टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र 30 जून तक बढ़ाया गया
- पर्यटकों को अतिरिक्त 15 दिन तक जंगल सफारी का अवसर मिलेगा
- इस सीजन में बाघों की साइटिंग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई
- एक सींग वाले गैंडे, हाथी और बारासिंघा प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं
- जून में जलस्रोतों के पास वन्यजीवों की गतिविधियां अधिक देखने को मिलती हैं
- पर्यटन सत्र बढ़ने से होटल, गाइड और परिवहन व्यवसाय को लाभ होगा
- वन्यजीव फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों ने निर्णय का स्वागत किया है

नव्य अयोध्या के साये में अवैध प्लाटिंग का खेल!

किसके संरक्षण में फल-फूल रहा भू-माफियाओं का साम्राज्य?

» रेलवे लाइन किनारे नियमों की धज्जियां, जेई की भूमिका पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का सपना साकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कथित अवैध प्लाटिंग और निर्माण का खेल प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नव्य अयोध्या परियोजना के समीप रेलवे लाइन से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन की प्लाटिंग और कॉलोनियों के विकास की शिकायतें सामने आ रही हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई कागजों तक सीमित रहती है। आरोपों के केंद्र में विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता सुरेन्द्र सिंह यादव का नाम चर्चा में है।

लोगों का कहना है कि अवैध निर्माणों का निरीक्षण तो होता है, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सूत्रों का दावा है कि रेलवे लाइन से सटे क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर लेआउट स्वीकृत कराने की कोशिशें भी चल रही हैं। वहीं कुछ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के नाम पर दबाव बनाकर कथित धन उगाही की जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय नागरिकों ने शासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं।

बुलडोजर गरीब की झोपड़ी पर ही यों ?

जब खेत की मेड़ पर बनी टीनशेड पर बुलडोजर गरजता है तो प्रशासन की सख्ती दिखाई देती है, लेकिन नव्य अयोध्या के आसपास अवैध प्लाटिंग की पूरी बस्तियां बसने लगें तो जिम्मेदारों की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? सवाल यह है कि नक्शा पास होने से पहले प्लॉट बिक रहे हैं या प्लॉट बिकने के बाद नियम बनाए जा रहे हैं? अगर सब कुछ वैध है तो जांच से डर कैसा, और अगर अवैध है तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? अयोध्या की जनता जवाब चाहती है, बहाने नहीं।

कोतवाली नगर की कमान संभाली, अपराध पर सख्ती पीड़ितों को भरोसा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जनपद में पुलिस विभाग के हालिया फेरबदल के बाद पूराकलंदर से स्थानांतरित होकर आए प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा ने गुरुवार को कोतवाली नगर का कार्यभार संभाल लिया। चार्ज ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में हर हाल में कानून व्यवस्था और लाइन ऑर्डर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

नवागत प्रभारी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ शत-प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कोई भी पीड़ित बिना डर उनके पास पहुंचकर अपनी समस्या रख सकता है। साथ ही उन्होंने अपराधियों और मनचलों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने जनता के बीच भय या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

14 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए चला बुलडोजर

» मकानों के साथ प्राचीन शिव मंदिर भी ध्वस्त

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। ककरही बाजार क्षेत्र में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मार्ग की जद में आने वाले कई मकानों को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी तोड़ दिया गया, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों को पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका था तथा कई बार नोटिस जारी कर निर्माण खाली करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मौके पर एडीएम राजस्व अमित भट्ट, एसडीएम सदर अरविंद कुमार और सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं एक प्रभावित मकान मालिक ने आरोप लगाया कि पहले परिक्रमा मार्ग का प्रस्तावित रूट दूसरी दिशा से था, बाद में परिवर्तन से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

चढ़ावे से राजनीति तक: आस्था की अदालत में उठे कई प्रश्न

» कमिश्नर कौशिक व प्राधिकरण सचिव श्रीवास्तव की याद दिला रहा राम मंदिर के चढ़ावे में हेर-फेर

» पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर तक कमीशन लेने से डरने लगे, दिल्ली से अयोध्या तक की भाजपा साइलेंट मोड में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

स्वराज इंडिया | अयोध्या | 11

राम के नाम पर कौन खेल गया करोड़ों का खेल?

महिपाल सिंह

दानपात्र पर घमासान

ट्रस्ट पर सवाल और संत की सीधी चेतावनी

राम के नाम पर खेल या विश्वास से खिलवाड़?

राम में हेराफेरी !

FOLLOW UP

अयोध्या । राम मंदिर बाबरी मस्जिद विभाग में केंद्र की नरसिंह राव की सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण जनवरी 1993 में किया था। बताते चले कि अधिग्रहित भूमि का रिसीवर कमिश्नर फैजाबाद को केंद्र सरकार ने नामित किया। कमिश्नर उसे समय राधेश्याम कौशिक रहे। उनके आधार पर विकास प्राधिकरण के सचिव सुनील श्रीवास्तव अधिग्रहित जमीन के मंदिरों की देखरेख करते थे। कई महीने बाद इन पर मंदिर की कीमती लकड़ियों राम मंदिरों की प्राचीन कलाकृतियों को हटाने के आरोप लगने लगे। लेकिन उस बार सरकारी तंत्र से कोई %महिपाल सिंह% बनने को तैयार नहीं हुआ। महिपाल सिंह वह नाम है जिसने चढ़ावे में हेर फेर की परतों को खोल दिया।

अब हम राम मंदिर के पुराने प्रसंगों विवादित परिसर के अधिग्रहण की ओर आपको ले चलते हैं। बताते है कि कुछ दिन बाद कमिश्नर राधेश्याम कौशिक का तबादला केंद्र सरकार में हो गया। दक्षिण भारत के दौरे पर जाते समय एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। बताते हैं कि उसी के कई महीने बाद प्राधिकरण सचिव सुनील श्रीवास्तव के इलाहाबाद आवास में डकैती पड़ी। डकैतों से मुठभेड़ में डकैतों ने उनकी जान ले ली। सरकारी सेवा काल में ही दोनों की असामयिक मृत्यु के बाद दोनों पर विवादित प्रसार में अधिग्रहित मंदिरों की संपत्तियों में हेर-फेर को भगवान राम लला के दंड से जोड़कर देखा जाने लगा। प्रसंग बस उल्लेख किया गया है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने या डराने कि नहीं है।इसके बाद इन दोनों घटनाओं से राम लला का डर अधिकारियों में ऐसा बैठा कि लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ठेकेदार से कमीशन लेने से हाथ खड़े कर दिये। ठेकेदार स्वयं बताने लगे कि वे 10 प्रतिशत मार्जिन पर अधिग्रहित क्षेत्र में कार्य कराते हैं। ठेकेदार बताते थे की विभाग में इंजीनियर राम जन्मभूमि के कार्य में कमीशन नहीं लेते। अब तो मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रबंधन के जिम्मे है। जब राम मंदिर के चढ़ावे में गोलमाल की खबर धीरे-धीरे उछलने लगी तो पुराने घटनाक्रमों का उल्लेख करना स्वाभाविक हो गया है। स्थानीय लोगो का कहना है कि भगवान के चढ़ावे में हेर-फेर का अफसरों को ऐसा दंड मिला की दिल्ली से लेकर अयोध्या तक का एक भी भाजपा नेता साथ खड़ा होने को ट्रस्ट परिवार के साथ तैयार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व डिप्टी सीएम बृजेश पाठक साइलेंट मोड में हैं। महिपाल सिंह के वीडियो वह %मीडिया की तथ्यात्मक खबरों से जिस तरह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की छीछालेदर हो रही है उससे फेस सेविंग कर पाना मुश्किल दिखता है। वैसे इस मामले में बीजेपी नेता डॉ. रजनीश सिंह पूर्व सूचना अधिकारी रहे डॉ0 मुरलीधर सिंह का पीएमओ को भेजा उच्चस्तरीय जांच कराने का पत्र, पूर्व सांसद विनय कटियार,महन्त कमल नयन दास पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह सहित अन्य हिन्दू संगठनों के नेताओ और जनता में उठ रहे मन्दिर में घोटाले के सवालों का जबाब अगर समय रहते निष्पक्ष नही मिला तो भारतीय जनमानस और अयोध्या की जनता की आस्था खंडित होगी।

अखिलेश यादव की पुत्री को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर सपा का विरोध

» साइबर थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।

इस प्रकरण को लेकर सपा अधिवक्ता सभा ने साइबर थाने पहुंचकर तहरीर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं। उन्होंने मांग की कि विवादित पोस्ट को तत्काल हटाया जाए तथा संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीर देने पहुंचे नेताओं ने साइबर पुलिस से निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सपा महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष शावेद जाफरी, महानगर अध्यक्ष लाल बहादुर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ईरान-अमेरिका समझौते का दावा

पाकिस्तान को फिर लगा कूटनीतिक झटका

ट्रंप बोले- अंतिम चरण में पहुंची वार्ता, ईरान ने समझौते की पुष्टि से किया इनकार

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक बार फिर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे पाकिस्तान के बजाय यूरोप में अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को पाकिस्तान के लिए एक बड़े कूटनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में पाकिस्तान खुद को अमेरिका-ईरान संवाद का संभावित मध्यस्थ बताने की कोशिश करता रहा है।

मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व समझौते के पक्ष में सकारात्मक रुख अपना रहा है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उनके अनुसार, ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और न ही उन्हें हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।

- ट्रंप ने अमेरिका-ईरान समझौते को अंतिम चरण में बताया।
- समझौते को यूरोप में अंतिम रूप दिए जाने का दावा किया गया।
- ईरान ने किसी अंतिम डील की पुष्टि से इनकार किया।
- परमाणु कार्यक्रम वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
- हालिया युद्धविराम के बावजूद दोनों देशों में अविश्वास कायम है।
- खार्ग द्वीप को लेकर पहले भी तनावपूर्ण बयान सामने आ चुके हैं।
- संभावित समझौते पर अब पूरी दुनिया और ऊर्जा बाजार की नजर टिकी हुई है।

हालांकि ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान ने किसी भी अंतिम समझौते की पुष्टि से इनकार कर दिया। तेहरान का कहना है कि वार्ता जारी है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कहना जल्दबाजी होगी। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा था। युद्धविराम, क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। इसके बावजूद बातचीत का जारी रहना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता आगे बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी राहत मिल सकती है। दूसरी ओर, पाकिस्तान की मध्यस्थता संबंधी उम्मीदों को झटका लगना उसकी क्षेत्रीय कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती माना जा रहा है।

पाकिस्तान को क्यों माना जा रहा झटका?

- पाकिस्तान स्वयं को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता था।
- ट्रंप ने समझौते का संभावित मंच यूरोप को बताया।
- वार्ता प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट नहीं दिख रही।
- इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक दावेदारी कमजोर पड़ सकती है।

परमाणु मुद्दा क्यों है सबसे अहम?

- अमेरिका की प्रमुख चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम है।
- पश्चिमी देशों को परमाणु हथियार निर्माण की आशंका रही है।
- ईरान लगातार अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता रहा है।
- किसी समझौते से क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं।

थाईलैंड की भावी महारानी प्रिंसेस भा का निधन, उत्तराधिकार को लेकर बढ़ी अनिश्चितता

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। थाईलैंड के शाही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देश के राजा महा वजिरालॉन्गकॉर्न की सबसे बड़ी पुत्री और राजगद्दी की प्रमुख दावेदार मानी जाने वाली राजकुमारी बज्रकितियाभा, जिन्हें प्रिंसेस भा के नाम से जाना जाता था, का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शाही महल द्वारा जारी आधिकारिक बयान में उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। उनके निधन से पूरे थाईलैंड में शोक की लहर फैल गई है।

प्रिंसेस भा पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों से कोमा में थीं। दिसंबर 2022 में वह अपने पालतू कुत्तों को टहला रही थीं, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। चिकित्सकीय जांच में हृदय संबंधी गंभीर संक्रमण का पता चला, जिसके कारण उनके मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी। इसके बाद उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

हाल के दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। संक्रमण के चलते शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और बैंकॉक के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रिंसेस भा

थाईलैंड की सबसे प्रभावशाली शाही हस्तियों में गिनी जाती थीं। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और न्याय, मानवाधिकार तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक समझ के कारण उन्हें भविष्य की महारानी के रूप में देखा जा रहा था।

उनके निधन के बाद थाईलैंड में राजसिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। 73 वर्षीय राजा महा वजिरालॉन्गकॉर्न ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी की औपचारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में 21 वर्षीय प्रिंस दिपंगकोर्न को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि उनकी कम उम्र और सीमित अनुभव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक और शाही गलियारों में अब इस बात पर नजरें टिकी हैं कि शाही परिवार उत्तराधिकार के मुद्दे पर आगे क्या निर्णय लेता है।

उत्तराखंड के 'गोल्डन बॉय' जसपाल राणा नहीं रहे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज खिलाड़ी, मशहूर कोच और एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है।

⇨ एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता, द्रोणाचार्य सम्मानित कोच और मनु भाकर के मार्गदर्शक के निधन से खेल जगत शोकाकुल

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 28 जून 1976 को जन्मे जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और 18 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए। बाद में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

जसपाल राणा को निशानेबाजी की प्रेरणा अपने पिता से मिली। महज 10 वर्ष की उम्र से उन्होंने पिस्टल शूटिंग का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1988 में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया।

हाल के वर्षों में वह भारतीय स्टार निशानेबाज मनु भाकर के कोच के रूप में चर्चा में रहे। उनके मार्गदर्शन में कई युवा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। खेल प्रशासन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही और वे उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके थे। जसपाल राणा का निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय निशानेबाजी में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया है।

जसपाल राणा की प्रमुख पदक उपलब्धियां

- 1994 – एशियाई खेल, हिरोशिमा–स्वर्ण पदक
- 1994 – कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप – स्वर्ण पदक
- 1998 – एशियाई खेल, बैंकॉक – स्वर्ण पदक
- 2002 – कॉमनवेल्थ गेम्स, मैनचेस्टर – कई स्वर्ण पदक
- 2006 – कॉमनवेल्थ गेम्स, मेलबर्न – पदक विजेता प्रदर्शन
- कुल उपलब्धि – अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 15 पदक, जिनमें कई स्वर्ण पदक शामिल।
- 1988 – 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, अहमदाबाद – रजत पदक

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com